**Pollution in the cities in the country**

4111. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) which are the first most polluted ten cities of the country;

(b) what is the level of permissible pollution and actual pollution in these respective cities; and

(c) what steps Government are taking to reduce the pollution in these cities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Vehicular and industrial emissions are the main causes of pollution in cities. National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur carried out ambient air quality monitoring in ten major cities of India Viz. Ahmedabad, Bombay Calcutta, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Cochin, Madras & Nagpur in collaboration with Central Pollution Control Board. At present, according to the air quality survey, the levels of sulphur dioxide & Nitrogen oxides in these major cities are well within the prescribed limits, while the levels of suspended particulate matter in these cites are on the higher side, which is due to the natural dusty conditions & increasing density of vehicular traffic. The standards for ambient air quality are as follows:

(Concentration in micro-gramme per cubic metre)

| Category | Suspended particulate | Sulphur dioxide | Carbon monoxide | Oxides of nitrogen |
|---|---|---|---|---|
| Industrial & Mixed Use . . . . . | 500 | 120 | 5000 | 120 |
| Residential & Rural Use . . . . . | 200 | 80 | 2000 | 80 |
| Sensitive Use . . . . . | 100 | 30 | 1000 | 30 |

Out of the ten cities covered the level of Sulphur dioxide has either decreased or remained unchanged in nine cities at the locations monitored. These cities are Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur, Ahmedabad, Hyderabad, Jaipur, Nagpur and Cochin. The level of Nitrogen dioxide has decreased in the city of Ahmedabad and remained unchanged in Calcutta, Madras, Cochin, Kanpur, Nagpur, Hyderabad and Jaipur. The level of suspended particulate matter has remained unchanged at most of the locations in all the ten cities. However, Nitrogen dioxide concentration has shown an increasing trend in both Delhi and Bombay.

(c) The steps taken to control pollution in cities of the country include the following:—

(i) Effluent and emission standards have been prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986;

(ii) A network of ambient air quality and ambient water quality monitoring stations have been set up;

(iii) Environmental guidelines have been evolved for siting and operation of industries;

(iv) Industries have been asked to comply with consent requirement of the State Pollution Control Board to keep the discharge of effluents and emission within the stipulated limits;

(v) Fiscal incentives are provided for installation of pollution control equipment and shifting of polluting industries from congested areas;

(vi) A time-bound action plan for control of emission from the 17 categories of polluting industries has been prepared in consultation with the State Government.

**वनों के विकास के लिये परियोजना**

4112. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से वनों के विकास के लिये कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ)** : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये एक वानिकी परियोजना प्रस्तुत की है। 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 9325 मिलियन रुपये है। इस परियोजना के प्रस्तावित मुख्य कार्यकलापों में अवक्रमित वनों का पुनरूद्धार, फार्म वानिकी, सुरक्षित क्षेत्रों की उन्नत प्रबंध व्यवस्था, वानिकी अनुसंधान, प्रशिक्षण विस्तार और प्रचार आदि शामिल है। परियोजना के अन्तर्गत लगभग 0.87 मिलियन हैक्टेयर भूमि को शामिल किये जाने और वृक्षारोपण के लिये 370 मिलियन पौद वितरित किये जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना प्रस्ताव वित्तीय सहायता के प्रावधान हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

**उत्तर प्रदेश में निर्धारित वन क्षेत्र**

4113. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वनों के लिये कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है और उसमें से कितना क्षेत्र वास्तव में वनाच्छादित है ;

(ख) वनों के लिये निर्धारित क्षेत्र और वास्तविक वनाच्छादित क्षेत्र की अखिल भारतीय स्तर पर क्या स्थिति है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में वानिकी की समस्या के कारण कितनी परियोजनायें स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है ; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ)** : (क) वन स्थिति (स्टेट आफ फारेस्ट) रिपोर्ट, 1991 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र तथा वास्तविक वनस्पति क्षेत्र क्रमशः 51,502 वर्ग कि.मी. तथा 33,609 वर्ग कि.मी. है।

(ख) वन स्थिति (स्टेट आफ फारेस्ट) रिपोर्ट, 1991 के अनुसार हमारे देश का दर्ज वन क्षेत्र तथा वास्तविक वनस्पति क्षेत्र क्रमशः 7,70,078 वर्ग कि.मी. तथा 6,39,182 वर्ग कि.मी. है;

(ग) 28-2-93 तक केन्द्र सरकार के समक्ष वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनेतर प्रयोजनों के लिये वन भूमि के उपयोग हेतु लंबित परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। **(नीचे देखिये)**

(घ) राज्य सरकार के सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव जैसे ही प्राप्त होते हैं उन पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाई की जाती है ।